ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 155-160**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- III, Issues-41, YEAR- July-Sept. 2026

अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर उपलब्ध अध्ययनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

धीरज कुमार,
2. डॉ0 मनोज कुमार सरोज

शोध अध्येता, समाजशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, 2. सहायक आचार्य– सी0 जी0 एन0 पी0 जी0 कॉलेज, गोला, खीरी (उ0प्र0) भारत

Received-29.07.2026, Revised-07.08.2026, Accepted-14.08.2026, E-mail:dheerajkumar9026424064@gmail.com

सारांशः अनुसूचित जातियों की शिक्षा सामाजिक असमानता, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक बहिष्करण एवं सशक्तिकरण को समझने का महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय आधार है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शिक्षा से संबंधित उपलब्ध अध्ययनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है तथा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। है। उपलब्ध साहित्य को चार प्रमुख विषयगत उपशीर्षकों–शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक बहिष्करण एवं भेदभाव, सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संस्थागत बाधाएँ तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा में लैंगिक आयाम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता एवं सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है, किंतु जातिगत भेदभाव, आर्थिक वंचना, सामाजिक बहिष्करण तथा संस्थागत बाधाएँ इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। साथ ही, जाति और लिंग का अंतर्संबंध अनुसूचित जाति महिलाओं की शिक्षा में विशिष्ट चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। निष्कर्षतः अनुसूचित जातियों की शिक्षा को केवल शैक्षिक पिछड़ेपन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना एवं असमान अवसरों से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में समझना आवश्यक है।

कुंजीभूत शब्द– शिक्षा, कलंक, सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक गतिशीलता, सशक्तिकरण, संस्थागत बाधाएं, लैंगिक असमानता,भेदभाव।

प्रस्तावना– भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से एक स्तरीकृत सामाजिक संरचना पर आधारित रहा है, जिसमें जाति व्यवस्था ने सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवसरों के वितरण को गहराई से प्रभावित किया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जातियाँ लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, अस्पृश्यता, भेदभाव तथा शैक्षिक वंचना का शिकार रहीं हैं। जिस करण शिक्षा, जो किसी भी समाज में सामाजिक गतिशीलता, समानता तथा सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम मानी जाती है, पारंपरिक रूप से इन समुदायों के लिए निषिद्ध अथवा अत्यंत सीमित रही है।

औपनिवेशिक काल में तथा उससे पूर्व इनको को औपचारिक शिक्षा से लगभग पूर्णतः वंचित रखा गया। सामाजिक नियमों, धार्मिक निषेधों तथा जातिगत पूर्वाग्रहों ने उन्हें ज्ञान–प्राप्ति से दूर रखा, जिससे उनकी सामाजिक स्थिति और अधिक कमजोर होती चली गई। अंबेडकर ने शिक्षा को सामाजिक मुक्ति, आत्मसम्मान तथा समानता प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन माना। उनके अनुसार शिक्षा वंचित समुदायों को सामाजिक बंधनों से मुक्त कर लोकतांत्रिक समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है (अंबेडकर,1979)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने समानता, सामाजिक न्याय तथा शिक्षा को लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूल आधारों के रूप में स्वीकार किया। संविधान ने राज्य को इनकी शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नति हेतु विशेष उपाय करने का दायित्व सौंपा गया। परिणामस्वरूप, शिक्षा संस्थानों में आरक्षण, छात्रवृत्ति योजनाएँ, निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास सुविधाएँ तथा विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू किए गए। इन प्रयासों के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों की शिक्षा तक पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। तथापि, मात्र अवसरों की उपलब्धता को सामाजिक समानता की पूर्ण प्राप्ति नहीं माना जा सकता, क्योंकि शैक्षिक अनुभवों एवं उपलब्धियों में विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा संरचनात्मक असमानताएँ अब भी विद्यमान हैं।

इसी संदर्भ में इन जातियों की शिक्षा समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। इस विषय पर अनेक अध्ययनों ने शिक्षा, जाति, वर्ग, लैंगिक सामाजिक बहिष्करण, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण जैसे विभिन्न आयामों का विश्लेषण किया है। इन अध्ययनों ने इन जातियों की शैक्षिक स्थिति, उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों तथा शिक्षा के माध्यम से होने वाले सामाजिक परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि इन जातियों की शिक्षा पर पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है, तथापि उपलब्ध अध्ययनों के सैद्धांतिक आधारों, प्रमुख निष्कर्षों तथा उनकी समाजशास्त्रीय व्याख्याओं का समग्र, तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण अपेक्षाकृत दुर्लभ है। परिणामस्वरूप, इस विषय से संबंधित उपलब्ध ज्ञान को एकीकृत समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता बनी हुई है। इसी अकादमिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर उपलब्ध प्रमुख अध्ययनों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। यह अध्ययन स्वयं अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति का प्रत्यक्ष विश्लेषण न करके, इस विषय पर उपलब्ध समाजशास्त्रीय अध्ययनों की समीक्षा एवं विश्लेषण पर केंद्रित है।

अनुसंधान पद्धति– प्रस्तुत अध्ययन एक गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का शोध है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की शिक्षा से संबंधित उपलब्ध साहित्य का समालोचनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है तथा उपलब्ध साहित्य का विषयगत आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार के प्राथमिक सर्वेक्षण अथवा क्षेत्रीय अध्ययन का उपयोग नहीं किया गया है।

साहित्य समीक्षा– प्रस्तुत शोध–पत्र में शोध विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य को उसके प्रमुख विषयगत निष्कर्षों के आधार पर चार प्रमुख उपशीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिससे साहित्य समीक्षा का सरलीकृत किया जा सके।

शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता– इस प्रथम उपशीर्षक में उन अध्ययनों का उल्लेख किया गया है जिनमे अनुसूचित जाति की सामाजिक गतिशीलता एव परिवर्तन को प्रभावित करने में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण मान गया है।

डिसूजा (1980) ने पंजाब में अनुसूचित जातियों की शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि राज्य द्वारा इन जातियों को विशेष शैक्षिक सुविधाएं दिये जाने पर भी इनके तथा अन्य समाज की जातियों के बीच शैक्षिक स्तर में पर्याप्त असमानता है और प्रगति की गति भी धीमी है।

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

सिंह (1987) ने जयपुर में किए अपने अध्ययन में, अनुसूचित जाति में सामाजिक परिवर्तन के एक नये आयाम की बात की। अध्ययन का मुख्य जोर सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक संरचना (जिसमें व्यावसायिक, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक भागीदारी, स्वास्थ्य व शिक्षा शामिल है।) पर था। उनके अनुसार ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का मुख्य कारण शिक्षा व बालकों को मिलने वाला वजीफा रहा।

संत (2002) ने वाराणसी नगर में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी सेवाओं में कार्यरत चमार उपजाति के सदस्यों पर किए गए अध्ययन में उच्च शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि उच्च शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण ने चमार समुदाय के सदस्यों की सामाजिक एवं आर्थिक उर्ध्वगामी गतिशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही, अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि इस समुदाय में व्यावसायिक गतिशीलता प्रतिस्पर्धात्मक योग्यता की अपेक्षा आरक्षण नीति से अधिक प्रभावित रही।

वानखेड़े (2006) ने अपने अध्ययन में बताया कि अनुसूचित जातियों के लिए उच्च शिक्षा सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण माध्यम है। अध्ययन में पाया गया कि आरक्षण एवं अन्य सकारात्मक कार्रवाई नीतियों ने उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच बढ़ाई है, किन्तु प्रतिकूल सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक पूर्वाग्रह तथा नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव के कारण उनकी प्रगति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच सकी।

थोराट व न्यूमैन (2008) ने अपने अध्ययन में शिक्षा को अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक समावेशन एवं सामाजिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। अध्ययन के अनुसार शिक्षा तक बढ़ती पहुँच ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार, उच्च शिक्षा तथा सार्वजनिक संस्थानों में भागीदारी के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार तथा सामाजिक समावेशन को सुदृढ़ करती है।

कुमार (2020) ने पाया कि शिक्षा अनुसूचित जातियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान, जागरूकता तथा सामाजिक सशक्तिकरण का प्रमुख माध्यम है। साथ ही, विभिन्न पीढ़ियों के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक भेदभाव तथा संस्थागत समस्याएँ अभी भी शैक्षिक प्रगति में बाधक बनी हुई हैं।

इंदु (2026) ने केरल के अनुसूचित जाति विकास विभाग की शिक्षा एवं कौशल विकास योजनाओं की रोजगार सृजन में भूमिका का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपनी शिक्षा एवं कौशल के अनुरूप रोजगार प्राप्त होने की संभावना अधिक थी। निष्कष से स्पष्ट हुआ कि शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम अनुसूचित जातियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने तथा शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सामाजिक बहिष्करण, भेदभाव एवं असमानता– इस विषय से संबंधित अध्ययनों में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के शैक्षिक अनुभवों में सामाजिक बहिष्करण, जाति.आधारित भेदभाव तथा असमानता के विभिन्न रूपों को रेखांकित किया गया है।

शर्मा (1974) ने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जातियों की शैक्षिक पिछड़ापन केवल संसाधनों की कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव एवं सामाजिक वंचना से भी जुड़ा हुआ है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि शैक्षिक असमानताएँ अनुसूचित जातियों और सामान्य वर्ग के बीच ही नहीं, बल्कि विभिन्न अनुसूचित जातियों तथा एक ही क्षेत्र की अनुसूचित जातियों के बीच भी विद्यमान हैं।

चिटनिस (1975) ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा का अध्ययन करते हुए पाया कि उच्च शिक्षा तक पहुँच मुख्यतः उन अनुसूचित जाति परिवारों के सदस्यों को प्राप्त हुई जो अपेक्षाकृत शिक्षित एवं सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में थे। अध्ययन में यह भी स्पष्ट हुआ कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली अनुसूचित जाति की महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों से आती थीं। लेखक ने निष्कर्ष दिया कि अनुसूचित जातियों के लिए संचालित विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों से समुदाय के भीतर भी नई शैक्षिक एवं सामाजिक असमानताएँ उभर रही हैं।

जेनकिंस एवं बार (2006) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में सामाजिक बहिष्कार तथा गरीबी जैसी संरचनात्मक बाधाएँ प्रमुख अवरोध हैं। अध्ययन के अनुसार ये कारण विद्यालयी शिक्षा तक उनकी पहुँच को प्रभावित करते हैं। शोध में इन समस्याओं के समाधान के लिए संदर्भ–विशिष्ट एवं समग्र सामाजिक नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया।

नीलकंदन एवं पाटिल (2012) ने अपने अध्ययन में बताया कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जाति आज भी सामाजिक समावेशन एवं बहिष्करण को प्रभावित करती है। अध्ययन में पाया गया कि संवैधानिक संरक्षण के बावजूद दलित छात्र शैक्षणिक एवं सामाजिक जीवन में जाति–आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्करण का सामना करते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति एवं समान अवसर प्रभावित होते हैं।

भारती (2012) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में संस्थागत भेदभाव, माता–पिता की निम्न शैक्षिक पृष्ठभूमि, अध्ययन के अनुकूल वातावरण का अभाव तथा सरकारी योजनाओं की अपर्याप्त जानकारी प्रमुख बाधाएँ हैं। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं है।

भोई (2023) ने अपने अध्ययन में बताया कि अनुसूचित जाति के छात्र उच्च शिक्षा में जाति–आधारित भेदभाव, सामाजिक कलंक, अपमान, वंचना तथा मनो.सामाजिक तनाव का अनुभव करते हैं। अध्ययन में पाया गया कि ये अनुभव उनकी शैक्षिक उपलब्धि एवं शैक्षणिक प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा सामाजिक बहिष्करण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करते हैं।

सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संस्थागत बाधाएँ– इस खंड में अनुसूचित जातियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाली सामाजिक–सांस्कृतिक परिस्थितियों, आर्थिक कठिनाइयों तथा संस्थागत अवरोधों पर केंद्रित अध्ययनों को रखा गया है।

चिटनिस (1972) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का निम्न शैक्षिक निष्पादन मुख्यतः उनकी कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है। बताया कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में उनका नामांकन कम है तथा अधिकांश छात्र निम्नस्तरीय संस्थानों में अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धियों में लिंग एवं सामाजिक असमानताएँ बनी रहती हैं।

विद्यार्थी एवं मिश्रा (1977) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जातियों में शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होने के बावजूद उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति बच्चों की शिक्षा में प्रमुख बाधा है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि छात्रवृत्ति एवं निःशुल्क शिक्षा जैसी सरकारी सुविधाओं के बावजूद गरीबी के कारण अनेक परिवार अपने बच्चों की नियमित शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाते।

चौधरी (2008) ने अपने अध्ययन में बताया कि भारत में उच्च शिक्षा शहरी एवं आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों के पक्ष में केंद्रित है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और कहा कि आर्थिक निर्भरता, ग्रामीण पृष्ठभूमि तथा सीमित शैक्षिक संसाधन उनकी शैक्षिक आकांक्षाओं एवं उच्च शिक्षा तक पहुँच में प्रमुख बाधाएँ है

चुघ (2011) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति एवं अन्य सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों में विद्यालय छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दर सामान्य वर्ग की तुलना में अधिक है। अध्ययन के अनुसार गरीबी, सामाजिक वंचना, क्षेत्रीय असमानताएँ तथा प्रतिकूल शैक्षिक परिस्थितियाँ ड्रॉपआउट के प्रमुख कारण हैं, जो उनकी शैक्षिक प्रगति एवं अवसरों को प्रभावित करती हैं।

भोई (2013) ने ओडिशा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा पर शिक्षा के निजीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि ऊँची फीस, आरक्षण के सीमित क्रियान्वयन, छात्रवृत्ति एवं संस्थागत सहयोग के अभाव के कारण उनकी उच्च शिक्षा तक पहुँच प्रभावित होती है। शोध में समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी सकारात्मक कार्रवाई तथा राज्य की सक्रिय भूमिका पर बल दिया गया।

नारायणन (2025) ने अपने अध्ययन में पाया कि केरल में अनुसूचित जाति के छात्रों की 12वीं की परीक्षा में सफलता दर अन्य छात्रों की तुलना में कम है। अध्ययन के अनुसार माता–पिता की कम शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पिछड़ापन तथा घर में अध्ययन की सुविधाओं का अभाव उनकी शैक्षिक उपलब्धि में प्रमुख बाधाएँ हैं। शोध में वित्तीय सहायता, बेहतर अध्ययन सुविधाएँ तथा संस्थागत सहयोग को उनकी शैक्षिक प्रगति के लिए आवश्यक बताया गया।

भोई (2025) ने अपने अध्ययन में पाया कि नवउदारवादी शिक्षा व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच और उसमें बने रहना कठिन हो गया है। अध्ययन के अनुसार आर्थिक संसाधनों की कमी, निजी शिक्षा की बढ़ती लागत, आरक्षण के कमजोर क्रियान्वयन तथा संस्थागत भेदभाव उनकी शैक्षिक प्रगति में प्रमुख बाधाएँ हैं। शोध में समावेशी शिक्षा, प्रभावी आरक्षण तथा वित्तीय सहायता को इन चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक बताया गया।

देहलवार और शर्मा (2026) ने मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा के बाद की छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि पर्याप्त बजट आवंटन के बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियाँ, सामाजिक भेदभाव तथा योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अध्ययन ने छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता, प्रभावी निगरानी तथा जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा में लैंगिक आयाम– इस विषय के अंतर्गत उपलब्ध साहित्य में अनुसूचित जाति छात्राओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले जाति, लिंग तथा सामाजिक–आर्थिक कारकों के अंतर्संबंध को समझने का प्रयास किया गया है।

दास (2013) ने अपने अध्ययन में पाया कि असम के अनुसूचित जाति समुदाय में शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अध्ययन के अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं के कारण अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता और शैक्षिक स्थिति संतोषजनक नहीं है। शोध में उनकी शैक्षिक उन्नति के लिए लक्षित नीतिगत एवं सामाजिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया गया।

रुचि (2013) ने अपने अध्ययन में तीन पीढ़ियों की अनुसूचित जाति महिलाओं की शैक्षिक गतिशीलता का विश्लेषण करते हुए पाया कि समय के साथ उनकी शिक्षा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अध्ययन में यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्तमान पीढ़ी की शैक्षिक स्थिति पूर्ववर्ती पीढ़ियों की तुलना में बेहतर है, किन्तु उच्च शिक्षा तक उनकी पहुँच अभी भी सीमित है, जिससे शैक्षिक उन्नति की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है।

गोस्वामी (2022) ने अध्ययन में पाया कि उच्च शिक्षा तक पहुँच में जाति, सामाजिक वर्ग तथा लिंग की असमानताएँ आज भी विद्यमान हैं। अध्ययन के अनुसार संसाधनों का असमान वितरण एवं सामाजिक बहिष्कार अनुसूचित जाति, विशेषकर महिलाओं, की उच्च शिक्षा तक पहुँच में प्रमुख बाधाएँ हैं। शोध में समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक असमानताओं को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

रेणुकुंतला व गुंडेमेडा (2023) ने अपने अध्ययन में पाया कि दलित महिला शोधार्थियों को उच्च शिक्षा में जाति एवं लिंग के आधार पर दोहरे भेदभाव, संस्थागत असमानताओं तथा सामाजिक बहिष्करण का सामना करना पड़ता है। अध्ययन के अनुसार आर्थिक पिछड़ापन, पारिवारिक दबाव तथा भेदभावपूर्ण शैक्षणिक वातावरण उनकी शोध प्रगति एवं मनोवैज्ञानिक कल्याण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। शोध में समावेशी एवं भेदभाव–मुक्त शैक्षणिक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मंडल (2026) ने अपने अध्ययन में पाया कि अनुसूचित जाति बालिकाओं की शिक्षा सामाजिक–आर्थिक स्थिति, पितृसत्तात्मक मान्यताओं, अभिभावकों की साक्षरता तथा आधारभूत शैक्षिक सुविधाओं से प्रभावित होती है। अध्ययन में यह भी बताया गया कि सरकारी योजनाएँ, मातृ सहयोग एवं सामुदायिक जागरूकता बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण– उपलब्ध साहित्य के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा को केवल नामांकन, साक्षरता अथवा शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। विभिन्न अध्ययनों को साथ रखकर देखने पर शिक्षा, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति, जातिगत संबंध, संस्थागत व्यवस्थाओं तथा लैंगिक संबंधों के बीच एक अंतर्संबंध दिखाई देता है। एक ओर शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक उन्नति, रोजगार, सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण का माध्यम बनती है, वहीं दूसरी ओर जाति आधारित भेदभाव, गरीबी, सामाजिक बहिष्करण तथा संस्थागत अवरोध शिक्षा के इन संभावित प्रभावों को सीमित करते हैं। इस प्रकार अनुसूचित जातियों की शैक्षिक स्थिति को व्यक्तिगत योग्यता की अपेक्षा सामाजिक अवसरों और संसाधनों के असमान वितरण के संदर्भ में समझना अधिक उपयुक्त है।

शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता से संबंधित अध्ययनों में शिक्षा की परिवर्तनकारी भूमिका प्रमुख रूप से सामने आती है। डिसूजा (1980) के अध्ययन से पता चलता है कि विशेष शैक्षिक सुविधाएँ उपलब्ध होने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों के बीच शैक्षिक असमानता बनी रही। इसके विपरीत, सिंह (1987) ने शिक्षा तथा छात्रवृत्ति को अनुसूचित जातियों में ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में रेखांकित किया। संत (2002) ने उच्च शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण को चमार समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक ऊर्ध्वगामी गतिशीलता से जोड़ा। इसी क्रम में वानखेड़े (2006) ने उच्च शिक्षा को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का माध्यम माना, जबकि थोराट एवं न्यूमैन (2008) ने शिक्षा को सामाजिक समावेशन, रोजगार और

सामाजिक गतिशीलता से जोड़ा। कुमार (2020) के अध्ययन में भी शिक्षा को सामाजिक–आर्थिक उत्थान, जागरूकता और सशक्तिकरण का माध्यम माना गया है। नवीन अध्ययन में इंदु (2026) ने शिक्षा एवं कौशल विकास को रोजगार क्षमता से जोड़ा है।

इन अध्ययनों को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखने पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षा सामाजिक गतिशीलता की संभावना उत्पन्न करती है, लेकिन शिक्षा का प्रभाव सामाजिक संरचना से स्वतंत्र नहीं है। उदाहरणतः संत (2002) के अध्ययन में आरक्षण की भूमिका दिखाई देती है, जबकि डिसूजा (1980) का अध्ययन यह बताता है कि विशेष सुविधाओं की उपलब्धता के बावजूद असमानता समाप्त नहीं हुई। वानखेड़े (2006) तथा कुमार (2020) के निष्कर्ष भी बताते हैं कि सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियाँ और भेदभाव शिक्षा से प्राप्त होने वाले लाभों को प्रभावित करते हैं। अतः शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का साधन तो माना जा सकता है, लेकिन उसे सामाजिक असमानताओं से स्वतः मुक्ति का साधन नहीं माना जा सकता।

जाति–आधारित सामाजिक बहिष्करण और भेदभाव से संबंधित अध्ययनों से शिक्षा और जाति–संबंधों का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। शर्मा (1974) ने शैक्षिक पिछड़ेपन को केवल संसाधनों की कमी से न जोड़कर उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव और सामाजिक वंचना से भी संबंधित माना। चिटनिस (1975) ने यह दिखाया कि उच्च शिक्षा तक पहुँच अपेक्षाकृत शिक्षित और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति वाले अनुसूचित जाति के परिवारों तक अधिक सीमित थी तथा विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों के बावजूद समुदाय के भीतर नई असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। जेनकिंस एवं बार (2006) ने सामाजिक बहिष्कार और गरीबी को अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में संरचनात्मक बाधाओं के रूप में रेखांकित किया। वहीं नीलकंदन एवं पाटिल (2012) ने शिक्षा व्यवस्था में जाति की भूमिका तथा जाति–आधारित भेदभाव और बहिष्करण की निरंतरता को सामने रखा। विनोद (2012) के अध्ययन में भी उच्च शिक्षा में संस्थागत भेदभाव और संस्थागत कमियों की ओर संकेत मिलता है। हाल के भोई (2025) के अध्ययन में जातिगत भेदभाव, सामाजिक कलंक, अपमान और मनो–सामाजिक तनाव को विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन से जोड़ा गया है।

इन अध्ययनों का समाजशास्त्रीय अर्थ यह है कि जाति केवल सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि शैक्षिक अवसरों और शैक्षिक अनुभवों को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक शक्ति भी है। विशेष रूप से जेनकिंस एवं बार (2006) का अध्ययन गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को संरचनात्मक बाधाओं के रूप में सामने लाता है, जबकि नीलकंदन एवं पाटिल (2012) और भोई (2025) शिक्षा संस्थानों में जाति के अनुभवात्मक और संस्थागत पक्ष को स्पष्ट करते हैं। इससे यह समझ विकसित होती है कि विद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर लेना ही सामाजिक समानता का प्रमाण नहीं हैय संस्थान के भीतर मिलने वाला व्यवहार और सामाजिक वातावरण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है।

सामाजिक–सांस्कृतिक, आर्थिक एवं संस्थागत बाधाओं से संबंधित साहित्य इस विश्लेषण को और व्यापक बनाता है। चिटनिस (1972) ने अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के निम्न शैक्षिक निष्पादन को कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा में कम भागीदारी से जोड़ा। विद्यार्थी एवं मिश्रा (1977) ने शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद गरीबी को प्रमुख बाधा माना। चौधरी (2008) ने ग्रामीण पृष्ठभूमि, आर्थिक निर्भरता और सीमित शैक्षिक संसाधनों को उच्च शिक्षा तक पहुँच में बाधक माना, जबकि चुघ (2011) ने गरीबी, सामाजिक वंचना, क्षेत्रीय असमानताओं और प्रतिकूल शैक्षिक परिस्थितियों को ड्रॉपआउट से जोड़ा।

इसी क्रम में भोई (2013) ने उच्च शिक्षा के निजीकरण, ऊँची फीस, आरक्षण के सीमित क्रियान्वयन तथा छात्रवृत्ति और संस्थागत सहयोग की कमी को अनुसूचित जाति की विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में बाधक बताया। नारायणन (2025) ने माता–पिता की कम शैक्षिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पिछड़ेपन और घर में अध्ययन सुविधाओं के अभाव को शैक्षिक उपलब्धि से जोड़ा। वहीं भोई (2025) ने नवउदारवादी शिक्षा व्यवस्था, निजी शिक्षा की बढ़ती लागत, आर्थिक संसाधनों की कमी तथा संस्थागत भेदभाव को उच्च शिक्षा में प्रवेश और बने रहने की समस्या से जोड़ा। देहलवार एवं शर्मा (2026) ने छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक कमियों, सामाजिक भेदभाव और जागरूकता के अभाव को रेखांकित किया।

इन अध्ययनों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा की उपलब्धता और शिक्षा तक वास्तविक पहुँच अलग–अलग सामाजिक स्थितियाँ हैं। विद्यालय या महाविद्यालय की उपलब्धता अपने आप में पर्याप्त नहीं है। परिवार की आर्थिक क्षमता, माता–पिता की शैक्षिक पृष्ठभूमि, ग्रामीण अथवा शहरी स्थिति, अध्ययन के लिए उपलब्ध संसाधन, शिक्षा की लागत, छात्रवृत्ति तथा संस्थागत सहयोगकृये सभी वास्तविक शैक्षिक अवसरों को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से शैक्षिक असमानता को केवल व्यक्ति की शैक्षिक आकांक्षा या क्षमता का परिणाम मानना समाजशास्त्रीय रूप से पर्याप्त नहीं होगा।

लैंगिक आयाम से संबंधित साहित्य अनुसूचित जातियों की शिक्षा में जाति और लिंग के अंतर्संबंध को स्पष्ट करता है। दास (2013) ने अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा में लैंगिक असमानता की ओर संकेत किया, जबकि रुचि (2013) ने तीन पीढ़ियों में शैक्षिक सुधार के बावजूद उच्च शिक्षा तक महिलाओं की सीमित पहुँच को रेखांकित किया। गोस्वामी (2022) ने जाति, सामाजिक वर्ग और लिंग के आधार पर उच्च शिक्षा में असमानताओं को सामने रखा। रेणुकुंतला एवं गुंडेमेडा (2023) ने दलित महिला शोधार्थियों के संदर्भ में जाति एवं लिंग के दोहरे भेदभाव तथा संस्थागत असमानता को रेखांकित किया। नवीन अध्ययन में मंडल (2026) ने सामाजिक–आर्थिक स्थिति, पितृसत्तात्मक मान्यताओं, अभिभावकों की साक्षरता तथा आधारभूत सुविधाओं को अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शिक्षा से जोड़ा है।

इन अध्ययनों से समाजशास्त्रीय रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुसूचित जाति महिलाओं और बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति को केवल जाति या केवल लिंग के आधार पर समझना पर्याप्त नहीं है। जाति, लिंग, वर्ग तथा संस्थागत परिस्थितियाँ एक–दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। परिणामतः अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए उत्पन्न शैक्षिक बाधाएँ कई स्तरों पर कार्य कर सकती हैं। इस प्रकार लैंगिक आयाम अनुसूचित जातियों की शिक्षा के अध्ययन को केवल "महिलाओं की शिक्षा" के प्रश्न से आगे ले जाकर सामाजिक असमानताओं के अंतर्संबंध के प्रश्न में बदल देता है।

समग्र रूप से समीक्षा किए गए सभी अध्ययनों से यह तस्वीर सामने आती है कि शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक–आर्थिक उन्नति, रोजगार, सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन शिक्षा का प्रभाव सामाजिक संरचना से अलग नहीं है। जातिगत बहिष्करण, आर्थिक वंचना, ग्रामीण–शहरी अंतर, परिवार की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, संस्थागत व्यवहार, राज्य की नीतियों का क्रियान्वयन तथा जाति और लिंग का अंतर्संबंध शैक्षिक अवसरों और परिणामों को प्रभावित करते हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों की शिक्षा को केवल "शैक्षिक पिछड़ेपन" की समस्या के रूप में देखना

पर्याप्त नहीं है इसे सामाजिक संरचना, संसाधनों के असमान वितरण, संस्थागत प्रक्रियाओं और सामाजिक संबंधों से निर्मित अवसरों की प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है।

निष्कर्ष– प्रस्तुत शोध का निष्कर्ष है कि शिक्षा अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक–आर्थिक उन्नति, रोजगार, सामाजिक समावेशन तथा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बावजूद जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्करण, गरीबी, सीमित संसाधन तथा संस्थागत बाधाएँ शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को प्रभावित करती हैं। साहित्य यह भी दर्शाता है कि अनुसूचित जातियाँ एक समान सामाजिक समूह नहीं हैं तथा उनके भीतर भी शैक्षिक अवसरों और संसाधनों में असमानताएँ मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त, जाति, लिंग और सामाजिक–आर्थिक स्थिति का अंतर्संबंध अनुसूचित जाति महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा को विशेष रूप से प्रभावित करता है। आरक्षण, छात्रवृत्ति और अन्य सकारात्मक कार्रवाई के बावजूद नीतियों का प्रभाव उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। अतः समग्र रूप से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों की शिक्षा में अवसरों का विस्तार हुआ है, लेकिन समान अवसरों और समान शैक्षिक परिणामों की प्राप्ति अभी भी एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय चुनौती है। इसलिए अनुसूचित जातियों की शिक्षा को केवल शैक्षिक पिछड़ेपन के प्रश्न के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना, असमान संसाधन–वितरण, संस्थागत प्रक्रियाओं और सामाजिक संबंधों से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में समझना अधिक उपयुक्त है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Ambedkar, B. R. (1979). Education: Its significance. In V. Moon (Ed.), Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and speeches (Vol. 3). Government of Maharashtra.
2. Bharati, V. (2012). Anusuchit Jati aur shiksha: Lucknow Vishwavidyalaya aur usse sambaddh mahavidyalayon ka samajshastriya adhyayan [Doctoral dissertation, Lucknow University]. Shodhganga. http://hdl.handle.net/10603/42272
3. Bhoi, D. (2013). Educational privatisation and access to higher education: Experiences of Scheduled Caste students in Odisha. Social Change, 43(3), 341–361. https://doi.org/10.1177/0049085713494289
4. Bhoi, D. (2023). Caste and everyday university life: Psycho-emotional experiences of Dalit students. In D. Bhoi & H. Gorringe (Eds.), Caste in everyday life: Experience and affect in Indian society (pp. 55–79). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-30655-6_3
5. Bhoi, D. (2025). Economic growth, development and education of Scheduled Castes: Line drawn from neoliberal era. Contemporary Voice of Dalit, 17(3), 277–293. https://doi.org/10.1177/2455328X21107
6. Chitnis, S. (1972). Education for equality: Case of Scheduled Castes in higher education. Economic and Political Weekly, 7(31/33), 1675–1681.
7. Chitnis, S. (1975). Education of the Scheduled Castes. Journal of Higher Education, 2. UGC, New Delhi.
8. Choudhary, S. K. (2008). Higher education in India: A socio-historical journey from ancient period to 2006–07. Journal of Educational Enquiry, 8(1).
9. Chugh, S. (2011). Dropout in secondary education: A study of children in slums of Delhi. National University of Educational Planning and Administration.
10. Das, R. (2013). Status of women in education among Scheduled Caste communities in Assam: A critical study. An International Peer Reviewed Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 1(1).
11. Dehalwar, K., & Sharma, S. N. (2026). Scheduled Caste students: Education and post-matric scholarships in Madhya Pradesh. Contemporary Voice of Dalit, 1–9. https://doi.org/10.1177/2455328X261438022
12. D'Souza, V. S. (1980). Educational inequalities among Scheduled Castes: A case study in the Punjab [Unpublished doctoral dissertation]. Panjab University.
13. Goswami, N. (2022). Unequal higher educational attainment across social backgrounds in West Bengal, India: A sociological analysis. Cogent Social Sciences, 8(1), Article 2144135. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2144135
14. Indhu, T. R. (2026). Education and skill development schemes of the Scheduled Caste Development Department of Kerala and role of enhancing employment among the marginalised communities. International Journal of Contemporary Research in Multidisciplinary, 5(1), 67–74.
15. Jenkins, R., & Barr, E. (2006). Social exclusion of Scheduled Caste children from primary education in India. UNICEF India.
16. Kumar, R. (2020). Change through education among Scheduled Castes and emerging problems: A sociological study. Journal of National Development, 33(2), 107–129.

17. Mandal, S. (2026). Determinants of Scheduled Caste (SC) parents' attitudes towards girls' academic continuation beyond secondary level. Policy Perspectives, 3(2), 32–36. https://doi.org/10.70798/PP/030200004
18. Narayanan, P. K. (2025). Educational disparities among Scheduled Caste students: An empirical study of plus two results in Kerala. International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR), 12(3), 123–132.
19. Neelakandan, S. M., & Patil, S. M. (2012). Complexities of inclusion and exclusion: Dalit students and higher education in India. Journal of Social Inclusion, 3(1), 89–108.
20. Renukuntla, A., & Gundemeda, N. (2023). Educational endeavours and unheeded tales: Mapping trajectories of Dalit women in a university. Sociological Bulletin, 72(4), 442–458. https://doi.org/10.1177/00380229231196718
21. Ruchi. (2013). Educational status and mobility of Scheduled Caste women: With special reference to Chohala Village Community in Jammu City. Acme International Journal of Multidisciplinary Research, 1(11).
22. Sharma, K. L. (1974). Educational inequalities among Rajasthan's Scheduled Castes. Economic and Political Weekly, 9(37), 1589, 1591–1592. https://www.jstor.org/stable/4363984
23. Singh, S. (1987). Scheduled Castes in India: Dimensions of social change. Gyan Publishing House.
24. Thorat, S., & Newman, K. S. (Eds.). (2008). Blocked by caste: Economic discrimination in modern India. Oxford University Press.
25. Vidyarthi, L. P., & Mishra, N. (1977). Harijan today: Sociological, economic, political, religious, and cultural analysis. Classical Publications. https://cir.nii.ac.jp/crid/1971712334766432918
26. Wankhede, G. G. (2006). Affirmative action and the Scheduled Castes: Access to higher education in India. In W. Allen et al. (Eds.), Higher education in global society: Achieving diversity, equity and excellence. Elsevier.
27. संत, एस. के. (2002). उच्च शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं विकासरू अनुसूचित जाति के विकासोन्मुख होने में उच्च शिक्षा की भूमिका एक समाजशास्त्रीय अध्ययन [पीएच.डी. शोधप्रबंध, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी]. शोधगंगा. http://hdl.handle.net/10603/289271

*****